भारत के इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में पश्चिम जर्मनी की रिपोर्ट

\+

17 3. श्री बिभूति मिश्र :
श्री क० ना तिवारी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी पुनर्निर्माण तथा ऋण निगम ने भारत के इस्पात उद्योग के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy): (a) A study on 'Development and Objects of Indian Iron & Steel Industry' was undertaken by M|s Kreditanstalt Fur Wiederaufbau—the West German Reconstruction and Loan Corporation—primarily for their own use. A copy of it has been received in the Ministry.

(b) A statement is placed on the Table of the House. [*Placed in Library See* No LT-170/67].

श्री बिभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है :

"it has been suggested that the construction of new mills should be postponed and further investments should be diverted for the expansion of already existing mills, as extension of existing facilities to their final stage would lower substantially the cost of production and improve the productivity of these mills"

साथ ही रा मैटीरियल जो हमारे पास है उसको हम किफायतशारी से खर्च करें। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा हुआ है :

"Under the contemplated extension projects, prority should be given to these susceptible of the most rapid implementation".

ये बहुत ही कीमती सजेशन उसने दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन सजेशंज को कार्यान्वित करने के बारे में क्या कर रही है ?

श्री चन्ना रेड्डी: जैसा मैंने अर्ज किया है यह कमेटी की खुद की रिपोर्ट है और अपनी ओर से इसने इसको दिया है। यह गवर्नमेंट की तरफ से बनाई हुई कमेटी नहीं है। इसके अलावा जो भी अच्छी बातें हैं रा मैटीरियल के बारे में या नई मिलों को बनाने के बजाय अभी तक जो एग्जिस्टिंग मिल्ज हैं उनके एक्सपेंशन के बारे में उन पर सरकार का ध्यान है और सरकार उन पर ध्यान दे रही है।

श्री बिभूति मिश्र : इन्होंने कमेटी नहीं बनाई यह ठीक है। लेकिन जो अच्छी अच्छी बातें इसने बताई हैं उनको कहां तक मानने के लिए सरकार कोशिश कर रही है ?

श्री चेन्ना रेड्डी. अभी तो जो एग्जिस्टिंग स्टील यूनिट्स हैं उनके एक्सपैंशन के काम पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। रा मटीरियल के बारे में जो सुझाव दिया गया है उस पर भी अमल करने की कोशिश की जा रही है।

श्री बिभूति मिश्र : रिपोर्ट में यह है कि आगे कोई नई मिल न बनाई जाए, स्टील मिल न बनाई जाए। सेलम में कारखाना खोलने के बारे में जो झगड़ा चला था क्या सरकार ने उस कारखाने का खोला जाना स्थगित कर दिया है इस रिपोर्ट को देखते हुए ?

श्री चेन्ना रेड्डी : नई मिल बनाने का जहां तक ताल्लुक है गवर्नमेंट के सामने चौथे प्लान की पूरी पिक्चर आ जाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा और उस वक्त इस पर सोचा जाएगा।

श्री बिभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। सरकार कहती है कि यह रिपोर्ट अच्छी है। इस रिपोर्ट

में कहा गया है कि आगे कोई कारखाना न लगाया जाये, बल्कि वर्तमान कारखानों को ही बढ़ाया जाये और उनमें दक्षता लाई जाये। जब सरकार इस रिपोर्ट को अच्छा मानती है तब क्या इसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ?

श्री क० ना० तिवारी : टेबल पर जो रीकमेंडेशन रखी गई है उसमें कहा गया है :

"The time required for expanding steel mills and for construction of ancillary undertakings such as dressing and sintering plants should be shortened substantially;"

मैं यह जानना चाहता हू कि इस रीकमेंडेशन का प्रभाव कौन कौनसी वर्तमान मिलों पर पड़ेगा और इसके अनुसार किन किन मिलों को बढ़ाया जायेगा ।

डा० चन्ना रेड्डी : इस वक्त एक तो दुर्गापुर के स्टील प्लांट की एक्सपेंशन का प्रोग्राम है । राउरकेला प्लांट के एक्सपेंशन की सेकंड स्टेज पूरी हुई है और थर्ड स्टेज के बारे में गौर किया जा रहा है।

Shri Indrajit Gupta: From the statement which has been laid, it seems that the West Germans are laying much more emphasis on the expansion of the existing projects rather than on the construction of new ones. But it does not seem evident from this summary, what I would like to know, whether, for example, in the case of further expansion project of Rourkela, they are agreeable to the maximum use of Indian manufactured structural materials, not raw materials, for the purpose of expansion of Rourkela or they want to import these materials also.

Dr. Chenna Reddy: It will be our basic policy to see that all the fabricated material that is available in the country goes into any expansion programme.

Shri Indrajit Gupta: What is the view of these Germans?

Dr. Chenna Reddy: There is no difference of opinion about that.

Mr. Speaker: Question Hour is over. We now take up S.N.Q. No. 4.

Dr. Karni Singh: Sir, I request that under rule 46, in regard to Question Nos. 175 and 188 which are of vital importance to the country, as they refer to devaluation, you may be kind enough to give your permission that these may be taken up after the Question Hour is over. I am sure, the Finance Minister will agree to that.

Mr. Speaker: No, no. We now take up the Short Notice Question.

श्री एम० ए० खां : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हू कि कल शाम की कार्यवाही में से कुछ अनफ्राज एक्सपंज कर दिये जायें, जो कि इस सभा की कार्यवाही में एन्टर हो चुके हैं। कल उपाध्यक्ष महोदय ने .....

Mr. Speaker: You want to raise the matter on what happened yesterday. Please don't raise it now, what happened yesterday. You may see me in my Chamber and we will consider. You cannot raise it here and now. कल उपाध्यक्ष ने जो कुछ किया, उसको अब नहीं उठाया जा सकता है ।

SHORT NOTICE QUESTION

Import Policy

SNQ. 4 Shrimati Tarkeshwari Sinha: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether there has been any delay in the finalisation of the Import Policy for 1967-68; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The suggestions of the Trade are considered in the Import-Export Advisory Council before the import policy is finalised. The meeting of the Council is to be held on 21st and 22nd April, 1967. The new Government wanted time to give full attention to this matter.